[2014] 14 एस सीआर 1124

आर. एन. अग्रवाल

बनाम

आर. सी. बंसल और अन्य

(आपराधिक अपील संख्या 2199-2201/2014)

14 अक्टूबर, 2014

[न्यायाधिपति एम. वाई. एक्बाल और न्यायाधिपति पिनाकी चंद्र घोस]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973- धारा 319, 5, 209 और 193-अपराध के लिए दोषी प्रतीत होने वाले अन्य व्यक्तियों के खिलाफ आगे बढ़ने की शक्ति – षड्यंत्र के अपराध के संबंध में छह व्यक्तियों के खिलाफ विशेष न्यायाधीश के समक्ष सीबीआई द्वारा आरोप पत्र दायर किया गया - छह व्यक्तियों को बुलाने का आदेश - इसके बाद तीन और लोगों को बुलाने के लिए विशेष न्यायाधीश के समक्ष आरोपी द्वारा आवेदन किया गया आरोपी के रूप में वे व्यक्ति, जिन्हें सीबीआई ने गवाह के रूप में उद्धृत किया था - विशेष न्यायाधीश ने अभियोजन पक्ष के गवाहों को बुलाने का आदेश पारित किया और साथ ही सीबीआई को इन व्यक्तियों को छोड़ने के लिए जांच अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया - उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश को रद्द कर दिया - की स्थिरता- आयोजित: धारा 5 के संदर्भ में, विशेष न्यायाधीश आरोपी को मुकदमे के लिए सौंपे बिना अपराध का

संज्ञान ले सकता है - तथ्यों पर, विशेष न्यायाधीश ने जांच के दौरान रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री पर विस्तार से विचार करने के बाद गवाहों के खिलाफ समन जारी किया - इस प्रकार, गवाहों के खिलाफ विशेष न्यायाधीश द्वारा समन जारी करने को रद्द करने वाला उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश टिकाऊ नहीं है - हालाँकि, विशेष न्यायाधीश के लिए यह आवश्यक नहीं था कि वह जांच अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए सीबीआई को निर्देश जारी करे।

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने माना गया:

1.1 जांच पूरी होने के बाद, सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1947 के साथ-साथ दंड संहिता के तहत मामलों से निपटने के लिए विशेष न्यायाधीश की अदालत में आरोप पत्र दायर किया। उक्त अधिनियम की धारा 5 में विशेष न्यायाधीश की प्रक्रिया एवं शक्तियाँ निर्धारित की गयी हैं। प्रावधान को मात्र पढ़ने से पता चलता है कि विशेष न्यायाधीश आरोपी को सुनवाई के लिए सौंपे बिना ही अपराध का संज्ञान ले सकता है और विशेष न्यायाधीश की अदालत को सत्र अदालत माना जाएगा। आरोपी व्यक्तियों की सुनवाई में विशेष न्यायाधीश मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों की सुनवाई के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेंगे। निर्विवाद रूप से, सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश या सहायक सत्र न्यायाधीश का पद धारण करने वाले व्यक्ति को विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है और वारंट मामलों की सुनवाई के लिए संहिता में

निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा। [पैरा 22,23][1141-डी-ई; 1142-जी-एच; 1143-ए]

1.2. विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश से पता चलता है कि उत्तरदाताओं के खिलाफ समन जारी करते समय, अदालत ने जांच के दौरान रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री पर विस्तार से विचार किया था। [पैरा 29] [1147-बी-सी]

1.3 आक्षेपित आदेश पारित करते समय, उच्च न्यायालय ने विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को उलट दिया। इसलिए, प्रथम दृष्टया, प्रतिवादियों के खिलाफ विशेष न्यायाधीश द्वारा समन जारी करने को रद्द करने वाला उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश कानून की दृष्टि से गलत है और इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है। हालाँकि, इस स्तर पर विशेष न्यायाधीश के लिए यह आवश्यक नहीं था कि वह मामले की जांच करने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए सीबीआई को निर्देश जारी करें। [पैरा 31] [1150-बी-सी]

अनिरुद्ध सेन बनाम राज्य (2006) 3 जेसीसी 2081 (दिल्ली), राज किशोर प्रसाद बनाम बिहार राज्य 1996 (2) पूरक एससीआर 125 (1996) 4 एससीसी 495; धरम पाल बनाम हरियाणा राज्य (2014) 3 एससीसी 306 ; हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य 2014 एस. सी. आर 1: (2014) 3 एससीसी 92; ए. आर. एंटूली बनाम रामदास श्रीनिवास नायक 1984 (2) एससीआर 914: (1984) 2 एस. सी. सी. 500; किशुन सिंह और अन्य बनाम बिहार राज्य 1993

(1) एससीआर 31: (1993) 2 एससीसी 16 ; रणजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य 1998 (2)पूरक एस. सी. आर 8: (1998) 7 एससीसी 149; हर्षद एस मेहता बनाम महाराष्ट्र राज्य 2001 (2) पूरक एस सी आर 577:(2001) 8 एस सी सी 257, तमिल नाडु राज्य बनाम कृष्णास्वामी नायडू 1979(3) एस सी आर 928: (1979)4 एस. सी. सी. 5; रघुबंस दुबे बनाम बिहार राज्य 1967 एससीआर 423: ए. आई. आर. 1967 एससी. 1167; मेसर्स स्विल लिमिटेडः बनाम दिल्ली राज्य और अन्य 2001 (1) पूरक एससीआर 527: (2001) 6 एस. सी. सी. 670;निसार और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 1994 (5) पूरक एससीआर 368: (1995) एस. सी. सी. 23; 1995 सी. आर. एल. एल. जे. 2118; रघुबंस दुबे बनाम बिहार राज्य (1967) 2 एस. सी. आर. 423-संदर्भित।

वाद कानून के संदर्भित

(2006) 3 जेसीसी 2081, संदर्भित किया गया है, पैरा 8,9,14,31

1996 (2) पूरक एस. सी. आर. 125, संदर्भित किया गया है, पैरा 9, 14, 15

(2014)3 एस. सी. सी. 306, संदर्भित किया गया है, पैरा 9, 18

2014 (2) एससीआर 1, संदर्भित किया गया है, पैरा 9,20.

1984 (2) एससीआर 914, संदर्भित किया गया है, पैरा 11, 24

1993 (1) एससीआर 31, संदर्भित किया गया है, पैरा 16,28

1998 (2) पूरक एस. सी. आर 8, संदर्भित किया गया है, पैरा 17

2001 (2) पूरक एससीआर 577, संदर्भित किया गया है, पैरा 25

1979 (3) एससीआर 928, संदर्भित किया गया है, पैरा 26

1967 एससीआर 423, संदर्भित किया गया है, पैरा 27

2001 (1) पूरक एससीआर 527, संदर्भित किया गया है, पैरा 30

1994 (5) पूरक एससीआर 368, संदर्भित किया गया है, पैरा 30

(1967)2 एससीआर 423, संदर्भित किया गया है, पैरा 30

आपराधिक अपील क्षेत्राधिकार : आपराधिक अपील संख्या 2199-2201/2014

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित सीआरएलएमसी संख्या 2955/2009, 575/2009 और 3779/2009 में दिनांक 02.02.2011 के निर्णय और आदेश से

अजीत कुमार सिन्हा, वरिष्ठ अधिवक्ता, अनूप के. श्रीवास्तव, गौरव धामा, राणा प्रताप सिंह और सुश्री साक्षी, अधिवक्ता अपीलार्थी के लिए।

अतुल यशवंत चिताले, वरिष्ठ अधिवक्ता , बसव प्रभु एस. पाटिल,अन्नाम डी. एन. राव, सुश्री नीलम जैन, सुश्री वैशाली आर., प्रदीप कुमारघोष, मंगल जीत मुखर्जी, संजय कुमार पाठक; राजीव नंदा, सुश्री वैष्णवी राव, बी. वी. बलराम दास, अरविंद कुमार शर्मा, श्रीमती प्रिया पुरी और रंजन दुबे, अधिवक्ता प्रतिवादी के लिए।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा दिया गया था-

न्यायाधिपति एम. वाई. एक्बाल,

1. अनुमति दे दी गई।

2. ये अपीलें फैसले के खिलाफ निर्देशित हैं और दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 2009 के सीआरएल.एमसी संख्या 2955 और 3779 और सीआरएल संशोधन में पारित आदेश दिनांक 2.2.2011। 2009 की संख्या 575 जहां दिल्ली उच्च न्यायालय ने विशेष न्यायाधीश सीबीआई कोर्ट रोहिणी के 10 जुलाई, 2009 के आदेश को रद्द करते हुए कथित दोषियों द्वारा दायर उपरोक्त धारा 482 आपराधिक याचिकाओं और जांच अधिकारी की धारा 397 आपराधिक पुनरीक्षण की अनुमति दी।

3. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि वर्ष 1983 में महारानी अवंती बाई सहकारी समिति नामक एक सोसायटी का गठन किया गया था और समय-समय पर सदस्यों को इसकी प्रबंध समिति द्वारा नामांकित किया गया था। वर्ष 1989 तक सोसायटी में 90 सदस्य थे और उसके बाद सदस्यों का नामांकन बंद कर दिया गया। हालाँकि, कई वर्षों तक सोसायटी को कोई ज़मीन आवंटित नहीं की गई और इस बीच इसके सदस्य सोसायटी के संचालन में उदासीन हो गए क्योंकि निर्माण किए जाने वाले फ्लैटों की लागत बहुत अधिक हो गई थी और उनकी पहुंच से बाहर हो गई थी। इस प्रकार समाज निष्क्रिय हो गया।

4. कुछ व्यक्ति जो सोसायटी के सदस्य नहीं थे, लेकिन दूरदर्शी और चतुर दिमाग वाले थे, वे इसके प्रबंधन को संभालने में रुचि रखते थे और उन्होंने दिल्ली विकास प्राधिकरण (संक्षेप में, 'डीडीए') से आवंटित भूमि का उपयोग अपने स्वयं के व्यक्तियों के लाभ के लिए किया।उन्होंने यह दिखाने के लिए सोसायटी के कुछ रिकॉर्ड बनाए कि सोसायटी के कई मूल सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया है और एक नई प्रबंध समिति का गठन किया गया है। सोसायटी के मूल सदस्यों के जाली त्याग पत्र द्वारा, नए सदस्यों को नामांकित दिखाया गया था और उस कार्यालय के अधिकारियों के साथ किसी प्रकार की आपराधिक समझ दर्ज करने के बाद सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के कार्यालय में जाली रिकॉर्ड जमा किए गए थे। यह आरोप लगाया गया है कि जाली दस्तावेजों के आधार पर, जिसमें सोसायटी की अवैध रूप से गठित प्रबंध समिति के सभी नए सदस्यों और आम सभा की बैठकों के मिनट भी शामिल थे, जो कभी आयोजित नहीं हुई थीं, डीडीए से भूमि आवंटन के लिए संपर्क किया गया था। सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार द्वारा यह प्रमाणित करके सहायता प्रदान की गई कि सभी बैठकें विधिवत आयोजित की गईं और सोसायटी के नए सदस्यों की एक सूची डीडीए को भेज दी गई। इसे स्वीकार करते हुए, डीडीए ने द्वारका में सोसायटी को 600 वर्ग मीटर का एक भूखंड आवंटित किया। वर्ष 1998 में सोसायटी के 90 सदस्यों को लाभ हुआ। ये सभी तथ्य सीबीआई की जांच के दौरान सामने आए।

5. जांच पूरी होने पर, सीबीआई ने छह लोगों के खिलाफ विशेष न्यायाधीश की अदालत में आरोप पत्र दायर किया, जिनमें से दो लोक सेवक थे।अन्य चार सोसायटी की फर्जी प्रबंध समिति के सदस्य थे, जिन्होंने जालसाजी आदि का सहारा लेकर निष्क्रिय सोसायटी पर कब्जा कर लिया था।

6. विशेष न्यायाधीश, सी.बी.आई. ने 23 जुलाई के आदेश द्वारा, 2008 में, सीबीआई द्वारा प्रस्तुत सामग्री का अवलोकन करने के बाद, भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी 420, 468 और 471 (संक्षेप में, 'आईपीसी') के साथ-साथ धारा 13(1) डी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दंडनीय अपराधों का संज्ञान लिया गया और उन छह लोगों को तलब करने का आदेश दिया, जिनका नाम सीबीआई ने अपने आरोप-पत्र में आरोपी व्यक्तियों के रूप में किया था, जिन पर एक-दूसरे के साथ साजिश रचकर अपराध करने का आरोप था। सभी आरोपियों के पेश होने के बाद, विशेष न्यायाधीश ने उन्हें दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 207 की आवश्यकता के अनुसार सभी दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान कीं और उसके बाद, मामले को 9 मार्च, 2009 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हालांकि, अगली तारीख से पहले सुनवाई के दौरान, आरोपी आर.एन.अग्रवाल ने सीआरपीसी की धारा 190 के साथ पठित धारा 193 के तहत एक आवेदन दायर किया। तीन और व्यक्तियों, मदन शर्मा (पीडब्लू-21), सुश्री सुजाता चौहान (पीडब्लू-23) और आर.सी. बंसल (पीडब्लू-30) को आरोपी के रूप में बुलाने के लिए विशेष

न्यायाधीश के समक्ष, जिन्हें सीबीआई ने अपने गवाहों के रूप में उद्धृत किया था। विद्वान विशेष न्यायाधीश ने उस आवेदन को 9 मार्च, 2009 को विचार के लिए रखा। हालांकि, उस दिन आरोपी आरएन अग्रवाल द्वारा दायर किए गए आवेदन के बारे में कुछ भी उल्लेख किए बिना मामले को आरोप पर बहस के लिए 5 मई, 2009 तक के लिए स्थगित कर दिया गया था। विशेष न्यायाधीश ने 5 जून, 2009 को उस आवेदन पर दलीलें सुनीं और फिर 10 जुलाई, 2009 के आदेश द्वारा उस आवेदन को स्वीकार कर लिया और अभियोजन पक्ष के गवाह मदन शर्मा, सुजाता चौहान और आरसी बंसल को बुलाया और साथ ही सीबीआई के निदेशक को उनके खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। इन तीनों व्यक्तियों को छोड़ देने के लिए आईपीसी की धारा 217 के तहत मामले के जांच अधिकारी।

7. दिनांक 1 जुलाई, 2009 के आदेश से व्यथित होकर, अभियोजन पक्ष के गवाह सुजाता चौहान और आर.सी. बंसल (यहां प्रतिवादी) ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के साथ पठित धारा 482, सीआरपीसी के तहत अलग-अलग याचिकाएं दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। जांच अधिकारी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज करने के लिए विशेष न्यायाधीश द्वारा दिए गए आदेश से व्यथित होकर सीबीआई ने भी पुनरीक्षण याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

8. उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश पर विचार करते हुए माना कि यह मामला पूरी तरह से अनिरुद्ध सेन बनाम राज्य (2006) 3 जेसीसी 2081 दिल्ली के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णय के अंतर्गत आता है। और परिणामस्वरूप विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को रद्द कर दिया।

9. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री अजीत कुमार सिन्हा ने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को अवैध और पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बिना बताया। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने अनिरुद्ध सेन के मामले (सुप्रा) में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया, जो राज किशोर प्रसाद बनाम बिहार राज्य, (1996)4 एससीसी 495 और इस न्यायालय द्वारा तय किए गए अनुपात का पालन करता था। यह माना गया कि मजिस्ट्रेट के पास आरोप-पत्र के कॉलम 4 में दिखाए गए व्यक्तियों को बुलाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। विद्वान वकील श्री सिन्हा ने आगे कहा कि धरम पाल बनाम हरियाणा राज्य, (2014) 3 एससीसी 306 के मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने विभिन्न निर्णयों पर विचार करने के बाद राज किशोर प्रसाद के मामले (सुप्रा) में दिए गए निर्णय को खारिज कर दिया। विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि मजिस्ट्रेट को गवाहों की जांच से पहले भी अन्य आरोपी व्यक्तियों को बुलाने का अधिकार है। श्री सिन्हा ने हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य (2014) 3 एससीसी 92 में इस

न्यायालय की एक अन्य संविधान पीठ के फैसले पर भी भरोसा किया और प्रस्तुत किया कि संविधान पीठ ने सहमति जताई दहराम पाल के मामले (सुप्रा) में अपनाए गए दृष्टिकोण के साथ।

10. श्री बसव प्रभु पाटिल, विद्वान वरिष्ठ वकील दूसरी ओर, प्रतिवादी की ओर से पेश होते हुए, उन्होंने कहा कि एक बार मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान ले लिया गया, तो आरोप-पत्र के कॉलम 4 में दिखाए गए व्यक्तियों को बुलाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। विद्वान वकील ने कहा कि धर्मपाल के मामले में संविधान पीठ द्वारा तय किया गया अनुपात मौजूदा मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है।

11. श्री प्रदीप के. घोष विद्वान वकील उपस्थित हुए प्रतिवादी नंबर 8 ने ए.आर.अंटुले बनाम रामदास श्रीनिवास नायक (1984) 2 एससीसी500 में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया और प्रस्तुत किया कि विशेष न्यायाधीश के समक्ष लंबित अन्यथा संहिता की धारा 193 आकर्षित नहीं होगी और इसकी कोई भूमिका नहीं है।

12. श्री अतुल चितले, विद्वान वरिष्ठ वकील उपस्थित हुए सी.बी.आई. ने तर्क दिया कि सी.बी.आई. ने प्रामाणिक तरीके से काम किया है और इसलिए, विशेष न्यायाधीश द्वारा की गई टिप्पणियाँ और अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए जारी किए गए निर्देश उत्पन्न नहीं होते हैं।

13. हमने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील द्वारा की गई दलीलों पर विचार किया है।

14. अनिरुद्ध सिंह के मामले (सुप्रा) में, याचिकाकर्ता को कॉलम 2 में दिखाते हुए आरोप पत्र दायर किया गया था क्योंकि याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई सामग्री उपलब्ध नहीं थी। मजिस्ट्रेट ने केवल आरोप-पत्र के कॉलम 4 में दर्शाए गए आरोपियों को ही तलब किया। हालाँकि, उत्तराधिकारी मजिस्ट्रेट ने बाद में याचिकाकर्ता सहित व्यक्तियों को बुलाया, जिन्हें आरोप-पत्र के कॉलम 2 में दिखाया गया था। उच्च न्यायालय ने राज किशोर प्रसाद मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले पर पूरी तरह भरोसा किया और ऐसा माना मजिस्ट्रेट के पास उस मामले के याचिकाकर्ता को बुलाने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था क्योंकि मुकदमे के दौरान कोई नई सामग्री/सबूत एकत्र नहीं किया गया था।

15. राज किशोर प्रसाद के मामले में, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि किसी नए अपराधी को बुलाने के लिए सीआरपीसी की धारा 209 के तहत शक्ति मजिस्ट्रेट के पास निहित नहीं थी, साथ ही उसके समक्ष की कार्यवाही 'जांच' नहीं थी। और उसके सामने मौजूद सामग्री 'साक्ष्य' नहीं है। इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया प्रश्न यह था कि क्या सीआरपीसी की धारा 209 के तहत किसी मामले की सुनवाई का उपक्रम किया जा सकता है। सत्र न्यायालय, संहिता की धारा 319 या सीआरपीसी के किसी अन्य प्रावधान के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए किसी अन्य व्यक्ति को आरोपी

के रूप में संबद्ध करता है। इस न्यायालय द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर इस प्रकार है: -

> "16. इस प्रकार हम यह मानते हैं कि सीआरपीसी की धारा 209 के तहत एक नए अपराधी को बुलाने की शक्ति एक मजिस्ट्रेट के पास इसके पाठ के स्पष्ट पाठ के साथ-साथ उसके सामने की कार्यवाही के आधार पर निहित नहीं थी, जो 'जांच' नहीं थी और उसके सामने सामग्री नहीं थी। 'सबूत' होने के नाते। जब ऐसी शक्ति निहित नहीं थी, तो इसका प्रयोग करने से इनकार को पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा सही नहीं किया जा सकता है, जो स्वयं सत्र न्यायालय हो सकता है जो प्रतिबद्धता पर मामले की प्रतीक्षा कर रहा है, केवल इस विशिष्ट आधार पर कि न्यायालय सत्र किसी भी स्थिति में, आरोपी को मुकदमे के लिए समन कर सकता है, साथ ही उस आरोपी को भी, जिसे उसके समक्ष मुकदमे के लिए प्रतिबद्ध किया जाना है। वर्तमान में यह स्पष्ट है कि धारा 319 सीआरपीसी के नियोजन का चरण नहीं आया है। सत्र न्यायालय का आदेश जिसमें मजिस्ट्रेट को अपीलकर्ता को उसके समक्ष मुकदमा चलाने के लिए प्रस्तावित आरोपी के साथ गिरफ्तार करने और तार्किक रूप से प्रतिबद्ध करने की आवश्यकता है, स्पष्ट रूप से अवैध है और अधिकार क्षेत्र

से परे है। चूंकि मजिस्ट्रेट के पास धारा 319 सीआरपीसी के तहत किसी व्यक्ति को आरोपी के रूप में जोड़ने की ऐसी कोई शक्ति नहीं है, जब वह धारा 209 सीआरपीसी के तहत किसी मामले को संभाल रहा हो, तो सत्र न्यायालय, पुनरीक्षण शक्तियों के कथित अभ्यास में उसे ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। आरंभ में पूछे गए प्रश्न का उत्तर इसी आलोक में दिया गया है। जब मामला सत्र न्यायालय के समक्ष प्रतिबद्धता के बाद आता है और साक्ष्य दर्ज किया जाता है, तो यह उसके द्वारा दर्ज किए गए साक्ष्य के आधार पर धारा 319 सीआरपीसी के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, यदि परिस्थितियां अपीलकर्ता के खिलाफ आगे बढ़ती हैं, तो उसे सम्मन कर सकता है। इसका उद्देश्य, प्रतिबद्ध अभियुक्त के साथ मुकदमा चलाना, उसे धारा 319 की उप-धारा (4) के तहत परिकल्पित आवश्यक सुरक्षा उपाय प्रदान करना है। इस तरह का कोर्स तत्काल मामले में और भी आवश्यक है जब योग्यता के आधार पर अभिव्यक्ति बड़े पैमाने पर की गई है। मजिस्ट्रेट, सत्र न्यायालय और उच्च न्यायालय के आदेश। कोई भी अन्य कोर्स अपीलकर्ता के लिए गंभीर पूर्वाग्रह का कारण बनेगा, हम तदनुसार आदेश देते हैं।"

6. किशुन सिंह और अन्य बनाम बिहार राज्य (1993) 2 एससीसी 16 के मामले में इस न्यायालय की एक डिवीजन बेंच इस सवाल पर विचार कर रही थी कि क्या सत्र न्यायालय, जिसमें एक मामला बिना किसी मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई के लिए सौंपा गया है स्वयं साक्ष्य दर्ज करते हुए, सीआरपीसी की धारा 173 के तहत प्रस्तुत पुलिस रिपोर्ट में नामित नहीं किए गए व्यक्ति को, पहले से ही नामित लोगों के साथ मुकदमा चलाने के लिए, संहिता की धारा 319 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, प्रश्न का उत्तर देते समय बुलाया जाए। संहिता के विभिन्न प्रावधानों पर विचार किया और निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचे:-

"13. फिर सवाल यह है कि क्या संहिता की धारा 319 के अनुसार, क्या संहिता के किसी अन्य प्रावधान में समान शक्ति का पता लगाया जा सकता है या क्या ऐसी शक्ति संहिता की योजना से निहित हो सकती है? हम पहले ही दो वैकल्पिक तरीकों के बारे में बता चुके हैं जिसमें आपराधिक कानून को गति प्रदान की जा सकती है; संहिता की धारा 154 के तहत पुलिस के पास सूचना दर्ज करके या मजिस्ट्रेट द्वारा शिकायत या सूचना प्राप्त होने पर। पूर्व में पुलिस द्वारा जांच की जाएगी और निष्कर्ष निकाला जा सकता है पुलिस

संहिता की धारा 173 के तहत रिपोर्ट करती है जिसके आधार पर संहिता की धारा 190(1)(बी) के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया जा सकता है।बाद के मामले में, मजिस्ट्रेट या तो संहिता की धारा 156(3) के तहत पुलिस को जांच का आदेश दे सकता है या धारा 190(1)(ए) या (सी) के तहत अपराध का संज्ञान लेने से पहले स्वयं धारा 202 के तहत जांच कर सकता है। जैसा भी मामला हो, संहिता की धारा 204 के साथ पढ़ें। एक बार जब मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान ले लेता है तो वह अपराधी पर मुकदमा चलाने के लिए आगे बढ़ सकता है (सिवाय जहां मामला धारा 191 के तहत स्थानांतरित किया गया हो) या उसे संहिता की धारा 209 के तहत मुकदमे के लिए सौंप सकता है यदि अपराध विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। जैसा कि पहले बताया गया है, संज्ञान अपराध का लिया जाता है, अपराधी का नहीं। रघुबंस दुबे बनाम बिहार राज्य मामले में इस न्यायालय ने कहा था कि एक बार किसी अपराध का संज्ञान लेने के बाद यह पता लगाना न्यायालय का कर्तव्य बन जाता है कि अपराधी वास्तव में कौन हैं और यदि न्यायालय को पता चलता है कि पुलिस द्वारा भेजे गए व्यक्तियों के अलावा कुछ अन्य व्यक्ति भी हैं। इसमें उन व्यक्तियों को समन करके उनके खिलाफ आगे बढ़ना उसका कर्तव्य है

क्योंकि अतिरिक्त अभियुक्तों को समन करना किसी अपराध का संज्ञान लेने से शुरू की गई कार्यवाही का हिस्सा है। वर्तमान संहिता लागू होने के बाद भी, कानूनी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है, इसके विपरीत हरेराम सत्पथी बनाम टीकाराम अग्रवाल में दुबे मामले के अनुपात की पुष्टि की गई थी। अभी तक कोई कठिनाई नहीं है.

14. अब हम अपनी यात्रा के महत्वपूर्ण बिंदु पर पहुंच गए हैं। संहिता की धारा 190(1) के तहत संज्ञान लेने के बाद, वारंट-मामलों में अदालत को आरोप तय करने की आवश्यकता होती है जिसमें कथित के समय और स्थान का विवरण शामिल होता है। अपराध और वह व्यक्ति (यदि कोई हो) जिसके विरुद्ध या वह चीज़ (यदि कोई हो) जिसके संबंध में यह किया गया था, लेकिन आरोप तय करने से पहले संहिता की धारा 227 यह प्रावधान करती है कि यदि, मामले के रिकॉर्ड पर विचार करने पर और उसके साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों के आधार पर, सत्र न्यायाधीश का मानना है कि आरोपी के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है, वह दर्ज किए जाने वाले कारणों से आरोपी को आरोपमुक्त कर देगा।ऐसा तभी होता है जब न्यायाधीश की राय एक जैसी हो तभी इसके लिए कोई आधार होता है यह

मानते हुए कि आरोपी ने अपराध किया है, वह आरोप तय करने के लिए आगे बढ़ेगा और आरोपी की दलील को अभिलिखित करेगा (धारा 228 के तहत)। यह तुरंत स्पष्ट हो जाता है कि आरोपी के खिलाफ आरोप तय करना है या नहीं, यह तय करने के सीमित उद्देश्य के लिए न्यायाधीश को मामले के रिकॉर्ड और उसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच करने की आवश्यकता होगी, जिसमें पुलिस रिपोर्ट, दर्ज किए गए गवाहों के बयान शामिल होंगे। संहिता की धारा 161 के तहत, जब्ती-ज्ञापन, आदि, आदि। यदि, इस सीमित उद्देश्य के लिए दिमाग लगाने पर, न्यायाधीश को पता चलता है कि आरोपी के अलावा उसके सामने अपराध के कमीशन में अन्य लोगों की मिलीभगत या संलिप्तता थी। उनके सामने रखी गई सामग्री से प्रथम दृष्टया यह पता चलता है कि उन्हें क्या कार्यवाही अपनानी चाहिए?"

16. हम पहले ही रघुबंस दुबे और हरेराम के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों के अनुपात से संकेत दे चुके हैं कि एक बार जब न्यायालय अपराध (अपराधी नहीं) का संज्ञान लेता है तो वास्तविक अपराधियों का पता लगाना न्यायालय का कर्तव्य बन जाता है और यदि ऐसा होता है इस निष्कर्ष पर कि पुलिस द्वारा मुकदमे के लिए रखे गए व्यक्तियों के अलावा कुछ अन्य लोग भी अपराध में शामिल हैं, यह अदालत

का कर्तव्य है कि उन्हें पहले से नामित लोगों के साथ मुकदमा चलाने के लिए बुलाया जाए क्योंकि उन्हें बुलाना केवल एक हिस्सा होगा संज्ञान लेने की प्रक्रिया। हमने पुरानी संहिता के तहत सत्र न्यायालय की दो संहिताओं की धारा 193 की भाषा में अंतर को भी इंगित किया है। मूल क्षेत्राधिकार की अदालत के रूप में किसी भी अपराध का संज्ञान लेने से तब तक रोका जाता है जब तक कि आरोपी इसके लिए प्रतिबद्ध न हो, जबकि वर्तमान संहिता के तहत आरोपी शब्द के स्थान पर केस शब्द का इस्तेमाल करने से प्रतिबंध कमजोर हो जाता है। इस प्रकार, एक सादे पढ़ने पर धारा 193 की वर्तमान स्थिति के अनुसार, एक बार जब मामला संहिता के तहत एक मजिस्ट्रेट द्वारा सत्र न्यायालय को सौंप दिया जाता है, तो मूल क्षेत्राधिकार की अदालत के रूप में किसी अपराध का संज्ञान लेने की सत्र न्यायालय की शक्ति पर लगाया गया प्रतिबंध हटा दिया जाता है। मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 209 के तहत मामले को सत्र न्यायालय में सौंपने पर धारा 193 की रोक हटा दी जाती है, जिससे सत्र न्यायालय को अपराध का संज्ञान लेने के लिए मूल क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय का पूर्ण और निरंकुश क्षेत्राधिकार मिल जाता है, जिसमें सम्मन भी शामिल होता है। व्यक्ति या व्यक्ति जिनकी अपराध के कमीशन में संलिप्तता को प्रथम दृष्टया अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री से इकट्ठा किया जा सकता है। पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने शेख लुत्फुर रहमान के मामले में संहिता की धारा 193 में पुराने संहिता के तहत बदलाव की उचित ही सराहना की:

"इसलिए, धारा 193 के तहत कानून अभी जो कल्पना और प्रावधान करना चाहता है, वह यह है कि अपराध बनाने वाली पूरी घटना का संज्ञान सत्र न्यायालय द्वारा प्रतिबद्धता के आधार पर लिया जाना है, न कि प्रत्येक व्यक्तिगत अपराधी को ऐसा प्रतिबद्ध होना चाहिए। या कि यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो सत्र न्यायालय उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने में शक्तिहीन हो जाएगा जिनके बारे में मुकदमे की शुरुआत में ही उसे पूरी तरह से आश्वस्त किया जा सकता है कि वे भी प्रथम दृष्टया अपराध के दोषी हैं.... एक बार जब मामला प्रतिबद्ध हो जाता है, तो धारा 193 की बाधा हटा दी जाती है या इसे दूसरे शब्दों में कहें तो स्थिति न्यायालय को निहित करने से संतुष्ट होती है।अपराध के किसी भी आरोपी को सम्मन करने के लिए पूर्ण अधिकार क्षेत्र के साथ सत्र।"

हम पुरानी धारा 193 और वर्तमान प्रावधान के बीच सामने आए अंतर से सम्मानजनक सहमत हैं।"

17. किशुन सिंह के मामले (सुप्रा) और राज किशोर प्रसाद के मामले (सुप्रा) में निर्धारित अनुपात रंजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1998) 7 एससीसी149 के मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के

समक्ष विचार के लिए आया था। किशुन सिंह के मामले (सुप्रा) में फैसले को अस्वीकार करते हुए, इस न्यायालय की पूर्ण पीठ ने राज किशोर प्रसाद के मामले (सुप्रा) पर भरोसा किया और कहा:

> "19. इसलिए प्रतिबद्धता के चरण से लेकर सत्र न्यायालय द्वारा संहिता की धारा 230 में निर्दिष्ट चरण तक पहुंचने तक अदालत केवल संहिता की धारा 209 में निर्दिष्ट अभियुक्तों से ही निपट सकती है। तब तक सत्र न्यायालय के लिए कोई मध्यस्थ चरण नहीं है आरोपियों की सूची में किसी अन्य व्यक्ति को शामिल करना।
>
> 20. इस प्रकार, एक बार जब सत्र न्यायालय प्रतिबद्ध आदेश के अनुसार अपराध का संज्ञान ले लेता है, तो एकमात्र अन्य चरण जब अदालत को अभियुक्तों की सूची में किसी अन्य व्यक्ति को जोड़ने का अधिकार होता है, वह साक्ष्य संग्रह तक पहुंचने के बाद होता है जब धारा 319 के तहत शक्तियां होती हैं। कोड लागू किया जा सकता है. हम आरोपियों की सूची में नए व्यक्ति या व्यक्तियों को शामिल करने की अनुमति देने के लिए सत्र न्यायालय के लिए कोई अन्य शक्ति खोजने में असमर्थ हैं। बेशक, अदालत के लिए उक्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए संपूर्ण साक्ष्य एकत्र होने तक इंतजार करना जरूरी नहीं है।

24. उपरोक्त कारणों से, हमें किशुन सिंह मामले में टिप्पणियों का समर्थन करना मुश्किल लगता है कि अपराध का संज्ञान लेने के लिए संहिता की धारा 193 के तहत सत्र न्यायालय की शक्तियों में उस व्यक्ति या व्यक्तियों को बुलाना शामिल होगा जिनकी मिलीभगत थी परीक्षण का कमीशन प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्रियों से एकत्र किया जा सकता है।"

18. इसी तरह का मामला धर्मपाल सिंह के मामले (सुप्रा) में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष विचार के लिए आया था क्योंकि इस न्यायालय द्वारा रंजीत सिंह के मामले और किशुन सिंह के मामले में विरोधाभासी दृष्टिकोण व्यक्त किए जाने के बाद मामले को संविधान पीठ के पास भेजा गया था। इस न्यायालय ने अब धर्मपाल सिंह के मामले, (2014) 3 एससीसी 306 में संविधान पीठ द्वारा इस प्रश्न को अंततः शांत कर दिया गया है।

19. संविधान पीठ ने रणजीत सिंह के मामले (सुप्रा) और राज किशोर प्रसाद के मामले में तय अनुपात को खारिज कर दिया है और माना है कि किशुन सिंह के मामले (सुप्रा) में निर्धारित अनुपात सही ढंग से तय किया गया है। संविधान पीठ ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

"34. किशुन सिंह मामले में व्यक्त विचार, हमारे विचार में, अधिक स्वीकार्य है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा यहां

पहले संदर्भित मामलों में माना गया है, मजिस्ट्रेट के पास अंतिम रिपोर्ट से असहमत होने की पर्याप्त शक्तियां हैं जो दायर की जा सकती हैं पुलिस अधिकारी संहिता की धारा 173(2) के तहत और आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पुलिस रिपोर्ट को खारिज कर देते हैं, जो धारा 319 के चरण तक पहुंचने तक सत्र न्यायालय के पास शक्ति नहीं है। उक्त स्थिति का परिणाम यह होगा कि यहां तक कि हालाँकि मजिस्ट्रेट के पास संहिता की धारा 173(2) के तहत दायर पुलिस रिपोर्ट से असहमत होने की शक्ति थी, लेकिन वह इस तरह की कार्यवाही का सहारा लेने में असहाय था, जबकि सत्र न्यायाधीश भी किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने में असमर्थ था। आरोपी को मुकदमे के लिए भेजा गया, जब तक कि सबूत पेश नहीं किए गए और आरोपी की ओर से गवाहों से जिरह नहीं की गई।

35. हमारे विचार में सीआरपीसी की धारा 173(2) के तहत उसके समक्ष प्रस्तुत पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लेने पर मामले को सत्र न्यायालय में भेजते समय मजिस्ट्रेट की एक भूमिका होती है। यदि मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट से असहमत है, तो वह दो विकल्प हैं. वह दायर की जा सकने वाली विरोध याचिका के आधार पर कार्यवाही कर सकता है, या

वह पुलिस रिपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया से असहमत होते हुए भी आरोपी को बुला सकता है। इसके बाद, यदि वह संतुष्ट हो जाए कि रिपोर्ट के कॉलम 2 में नामित व्यक्तियों के खिलाफ मामला बनाया गया है, तो उक्त व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए आगे बढ़ें या यदि वह संतुष्ट है कि मामला बनाया गया है, जो न्यायालय द्वारा विचारणीय है। सत्र न्यायालय, वह मामले में आगे बढ़ने के लिए मामले को सत्र न्यायालय को सौंप सकता है।

39. यह हमें अगले प्रश्न पर ले जाता है कि क्या धारा 209 के तहत मजिस्ट्रेट को मामले को सत्र न्यायालय में भेजने से पहले अपराध का संज्ञान लेना आवश्यक था। यह सर्वविदित है कि किसी अपराध का संज्ञान केवल एक बार ही लिया जा सकता है। ऐसी स्थिति में, एक मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान लेता है और फिर मामले को सत्र न्यायालय को सौंप देता है, अपराध का नए सिरे से संज्ञान लेने और उसके बाद समन जारी करने का सवाल कानून के अनुरूप नहीं है। यदि अपराध का संज्ञान लिया जाना है, तो इसे मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायालय द्वारा लिया जा सकता है। संहिता की धारा 193 की भाषा बहुत स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि एक बार जब मामला विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा

सत्र न्यायालय को सौंप दिया जाता है, तो सत्र न्यायालय मूल क्षेत्राधिकार मान लेता है और वह सब कुछ ऐसे क्षेत्राधिकार की धारणा के साथ चलता है। इसलिए, धारा 209 के प्रावधानों को यह समझना होगा कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने पुलिस रिपोर्ट से यह पता लगाने पर कि मामला सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, मामले को सत्र न्यायालय में सौंपने में निष्क्रिय भूमिका निभाई। न ही आंशिक संज्ञान मजिस्ट्रेट द्वारा लिए जाने और आंशिक संज्ञान विद्वान सत्र न्यायाधीश द्वारा लिए जाने का कोई प्रश्न ही नहीं हो सकता।

40. मामले के उस दृष्टिकोण में, हमें किशुन सिंह मामले में व्यक्त विचारों से सहमत होने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि सत्र न्यायालय के पास किसी मामले को सौंपने का अधिकार क्षेत्र है, ताकि अपराधियों के रूप में नामित नहीं किए गए व्यक्तियों के अपराधों का संज्ञान लिया जा सके। लेकिन मामले में किसकी मिलीभगत रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्रियों से स्पष्ट होगी। इसलिए, साक्ष्य दर्ज किए बिना भी, धारा 209 के तहत प्रतिबद्ध होने पर सत्र न्यायाधीश पुलिस रिपोर्ट के कॉलम 2 में दिखाए गए लोगों को पहले से ही नामित लोगों के साथ मुकदमा चलाने के लिए बुला सकते हैं।"

20. हरदीप सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2014) 3 एससीसी 92 में एक अन्य संविधान पीठ के फैसले में इस न्यायालय ने न्यायालय की शक्तियों पर चर्चा करते हुए धरम पाल के मामले में अपनाए गए दृष्टिकोण से सहमति व्यक्त की और निम्नानुसार कहा: -

> "53. इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से स्पष्ट है कि जब तक मामला अदालत द्वारा जांच या सुनवाई के चरण तक नहीं पहुंच जाता, तब तक सीआरपीसी की धारा 319 के तहत शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। वास्तव में, इस प्रस्ताव को संविधान पीठ द्वारा परेशान नहीं किया गया है। धरम पाल (सीबी) में। उस विवाद को एक ऐसी स्थिति की कल्पना करते हुए हल किया गया था जिसमें अदालत प्रक्रियात्मक देरी से चिंतित थी और उसकी राय थी कि सत्र न्यायालय को किसी ऐसे व्यक्ति को निर्देश देने के लिए सीआरपीसी की धारा 319 के चरण तक पहुंचने तक इंतजार नहीं करना चाहिए, जो सामना नहीं कर रहा है। मुकदमा, एक आरोपी के रूप में पेश होने और मुकदमे का सामना करने के लिए। हम संविधान पीठ द्वारा दी गई व्याख्या से पूरी तरह सहमत हैं कि धारा 193 सीआरपीसी सत्र न्यायालय को एक बार मामला सौंपे जाने के बाद आरोपी को जोड़ने के लिए मूल क्षेत्राधिकार की शक्ति प्रदान करती है। :

54. हमारी राय में, जांच का चरण अपने सख्त कानूनी अर्थों में किसी भी सबूत पर विचार नहीं करता है, न ही विधायिका इस पर विचार कर सकती है क्योंकि साक्ष्य का चरण अभी तक नहीं आया है। अदालत के पास अभियोजन पक्ष द्वारा एकत्र की गई एकमात्र सामग्री है और इस स्तर पर अदालत प्रथम दृष्टया यह पता लगाने के लिए अपना दिमाग लगा सकती है कि क्या कोई व्यक्ति, जो आरोपी हो सकता है, गलत तरीके से दोषी ठहराए जाने से छूट गया है। या अभियोजन एजेंसियों द्वारा जानबूझकर बाहर रखा गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए यह और भी आवश्यक है कि जांच और अभियोजन एजेंसियों ने उन व्यक्तियों को अदालत के सामने लाने में निष्पक्षता से काम किया है जो मुकदमा चलाने के लायक हैं और किसी भी व्यक्ति को जानबूझकर बचाया जाने से रोका जा सके जब उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए था। यह न्यायिक प्रणाली में विश्वास पैदा करने के लिए आवश्यक है, जिससे अदालत को जांच के चरण में भी ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार दिया जाना चाहिए और यही कारण है कि विधायिका ने सीआरपीसी की धारा 319 में जानबूझकर अलग-अलग शब्दों, अर्थात् पूछताछ या परीक्षण का उपयोग किया है।"

21. संविधान पीठ ने इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार दिया:-

"117.1. धरम पाल मामले में, संविधान पीठ ने पहले ही माना है कि किसी अपराध का संज्ञान लेने के बाद ऐसे व्यक्ति के खिलाफ संज्ञान लिया जा सकता है जिसका नाम आरोपी के रूप में नहीं है, लेकिन जिसके खिलाफ जांच पूरी होने के बाद पुलिस द्वारा दायर कागजात से सामग्री उपलब्ध है। धारा 193 सीआरपीसी के तहत संज्ञान लिया जा सकता है और सत्र न्यायाधीश को अतिरिक्त आरोपी को बुलाने के लिए सीआरपीसी की धारा 319 के तहत "सबूत" उपलब्ध होने तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है।

117.2. सीआरपीसी की धारा 319 महत्वपूर्ण रूप से दो अभिव्यक्तियों का उपयोग करती है जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए यानी (1) पूछताछ (2) परीक्षण। चूंकि आरोप तय होने के बाद मुकदमा शुरू होता है, इसलिए किसी जांच को केवल प्री-ट्रायल जांच ही समझा जा सकता है। धारा 200, 201, 202 सीआरपीसी और धारा 398 सीआरपीसी के तहत पूछताछ धारा 319 सीआरपीसी के तहत आने वाली जांच की प्रजातियां हैं। इस तरह की पूछताछ के दौरान अदालत का उपयोग धारा 319 सीआरपीसी के तहत शक्ति के प्रयोग के लिए मुकदमा शुरू होने के बाद अदालत में दर्ज

किए गए सबूतों की पुष्टि के लिए किया जा सकता है और एक आरोपी को जोड़ने के लिए भी किया जा सकता है जिसका नाम आरोप-पत्र के कॉलम 2 में दिखाया गया है।

117.3. उपरोक्त स्थिति को देखते हुए सीआरपीसी की धारा 319 में "साक्ष्य" शब्द को मोटे तौर पर समझा जाना चाहिए न कि शाब्दिक रूप से, यानी मुकदमे के दौरान लाए गए साक्ष्य के रूप में।

117.4. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि धारा 319 सीआरपीसी के तहत जिस व्यक्ति के खिलाफ सामग्री का खुलासा किया गया है उसे मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया जाता है और ऐसी स्थिति में धारा 319 (4) सीआरपीसी के तहत ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही संज्ञान लेने के चरण से शुरू होनी है, अदालत की जरूरत है प्रतिपरीक्षा द्वारा परीक्षण के लिए बुलाए जाने वाले प्रस्तावित अभियुक्त के विरुद्ध सबूतों की प्रतीक्षा न करें।"

22. जैसा कि ऊपर देखा गया है, जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के तहत मामलों से निपटने के लिए विशेष न्यायाधीश की अदालत में आरोप पत्र दायर किया। विशेष न्यायाधीश की प्रक्रिया और शक्तियां उक्त अधिनियम की धारा 5 में

निर्धारित की गई हैं, बेहतर सराहना के लिए, अधिनियम की धारा 5 को यहां नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है: -

"5.विशेष न्यायाधीश की प्रक्रिया और शक्तियाँ। —

(1) एक विशेष न्यायाधीश अभियुक्तों को सुनवाई के लिए सौंपे बिना अपराधों का संज्ञान ले सकता है और अभियुक्तों की सुनवाई में मजिस्ट्रेटों द्वारा वारंट मामलों की सुनवाई के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का 2) द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेगा।

(2) एक विशेष न्यायाधीश, किसी ऐसे व्यक्ति का साक्ष्य प्राप्त करने की दृष्टि से, जिसके बारे में माना जाता है कि वह किसी अपराध में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल था, या उसकी जानकारी रखता था, ऐसे व्यक्ति को पूर्ण और सच्चा खुलासा करने की शर्त पर क्षमा कर सकता है। अपराध से संबंधित उसकी जानकारी में मौजूद सभी परिस्थितियों और संबंधित प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह उसके अपराध में मुख्य या दुष्प्रेरक के रूप में हो और इस प्रकार दिया गया कोई भी क्षमा धारा की उप-धारा (1) से (5) के प्रयोजनों के लिए होगा। दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 के 2) के 308 को उस संहिता की धारा 307 के तहत प्रस्तुत किया गया माना जाएगा।

(3) उप-धारा (1) या उप-धारा (2) में दिए गए प्रावधानों के अलावा, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 के 2) के प्रावधान, जहां तक वे इस अधिनियम के साथ असंगत नहीं हैं, लागू होंगे। एक विशेष न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाही; और उक्त प्रावधानों के प्रयोजनों के लिए, विशेष न्यायाधीश के न्यायालय को सत्र न्यायालय माना जाएगा और पहले अभियोजन चलाने वाला व्यक्ति एक विशेष न्यायाधीश को लोक अभियोजक माना जाएगा।

(4) विशेष रूप से और उप-धारा (3) में निहित प्रावधानों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 326 और 475 के प्रावधान, जहां तक संभव हो, लागू होंगे विशेष न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाही पर लागू हो और उक्त प्रावधानों के प्रयोजनों के लिए, एक विशेष न्यायाधीश को मजिस्ट्रेट माना जाएगा।

(5) एक विशेष न्यायाधीश अपने द्वारा दोषी ठहराए गए किसी भी व्यक्ति को उस अपराध की सजा के लिए कानून द्वारा अधिकृत कोई भी सजा दे सकता है जिसके लिए ऐसे व्यक्ति को दोषी ठहराया गया है।

(6) एक विशेष न्यायाधीश, इस अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध की सुनवाई करते समय, आपराधिक कानून संशोधन

अध्यादेश, 1944 (1944 का अध्यादेश 38) के तहत एक जिला न्यायाधीश द्वारा प्रयोग की जाने वाली सभी शक्तियों और कार्यों का प्रयोग करेगा।"

23. प्रावधान को मात्र पढ़ने से पता चलता है कि विशेष न्यायाधीश आरोपी को सुनवाई के लिए सौंपे बिना अपराध का संज्ञान ले सकता है और विशेष न्यायाधीश की अदालत को सत्र अदालत माना जाएगा। आरोपी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने में विशेष न्यायाधीश मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों की सुनवाई के लिए दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेंगे। निर्विवाद रूप से, सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश या सहायक सत्र न्यायाधीश का पद धारण करने वाले व्यक्ति को विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है और वारंट मामलों की सुनवाई के लिए संहिता में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा।

24. ए.आर. अंतुले (सुप्रा) के मामले में संविधान पीठ का विचार था कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत नियुक्त विशेष न्यायाधीश को विशेष रूप से छोड़कर उच्च न्यायालय के तहत कार्य करने वाले मूल क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय को प्रदत्त सभी शक्तियां प्राप्त हैं। अधिनियम के तहत प्रदान किया गया। बेंच ने कहा:-

"27.....विशेष न्यायाधीश की अदालत की स्थापना करते समय इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि

सार्वजनिक जीवन में उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर ऐसी अदालत द्वारा मुकदमा चलाए जाने की संभावना है, निर्धारित योग्यता यह थी कि व्यक्ति को विशेष न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए या तो एक सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश या सहायक सत्र न्यायाधीश होना चाहिए। ये तीन प्रतिष्ठित व्यक्ति एक मजिस्ट्रेट के स्तर से ऊपर हैं। योग्यता निर्धारित करने के बाद, विधायिका अपराधों का संज्ञान लेने के लिए एक विशेष न्यायाधीश को शक्ति प्रदान करने के लिए आगे बढ़ी। जिसकी सुनवाई के लिए विशेष क्षेत्राधिकार वाली एक विशेष अदालत की स्थापना की जा रही थी। यदि किसी विशेष न्यायाधीश को अपराधों का संज्ञान लेना है, तो वास्तव में ऐसे अपराधों के मुकदमे की प्रक्रिया निर्धारित करनी होगी। अब संहिता विभिन्न अदालतों द्वारा मामलों की सुनवाई के लिए अलग-अलग प्रक्रियाएं निर्धारित करती है। सत्र न्यायालय के समक्ष किसी मामले की सुनवाई की प्रक्रिया अध्याय XVIII में निर्धारित की गई है, मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों की सुनवाई अध्याय XIX में निर्धारित की गई है और इसमें शामिल प्रावधानों को पूरा किया गया है। दोनों प्रकार के मामले मजिस्ट्रेट के समक्ष आते हैं, अर्थात् पुलिस रिपोर्ट पर या पुलिस रिपोर्ट के अलावा।

अध्याय XX सम्मन मामलों की सुनवाई के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है

मजिस्ट्रेट और अध्याय XXI सारांश परीक्षण के लिए प्रक्रिया निर्धारित करता है। अब जब एक नई आपराधिक अदालत स्थापित की जा रही थी, तो विधानमंडल ने सीआरपीसी की धारा 6 के तहत अदालतों के पदानुक्रम में अपनी तुलनात्मक स्थिति प्रदान करने का पहला कदम उठाया, इसे कमोबेश सत्र न्यायालय के तुलनीय स्तर पर लाया, लेकिन किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए स्तर के आधार पर तुलना से उत्पन्न भ्रम को देखते हुए, धारा 8(1) में ही यह स्पष्ट कर दिया गया था कि यह सत्र न्यायालय नहीं है क्योंकि यह धारा 193 सीआरपीसी के अनुसार प्रतिबद्धता के बिना अपराधों का संज्ञान ले सकता है। निस्संदेह धारा 8 (3) में यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया था कि धारा 8 की उप-धारा (1) और (2) के प्रावधानों के अधीन, विशेष न्यायाधीश के न्यायालय को जूरी के बिना या बिना जूरी मूल्यांकनकर्ताओं की सहायता के मामलों की सुनवाई करने वाला सत्र न्यायालय माना जाएगा।

5. हर्षद एस. मेहता बनाम महाराष्ट्र राज्य (2001) 8 एससीसी 257 के मामले में बेंच ने विशेष न्यायालय

(प्रतिभूतियों में लेनदेन से संबंधित अपराधों का परीक्षण) अधिनियम 1992 के तहत मामले से निपटते हुए पाया कि विशेष अदालत एक विशेष अदालत है अधिनियम की धारा 3(2) के तहत अपराधों के संबंध में क्षेत्राधिकार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत विशेष अदालत की तरह इसका मूल आपराधिक क्षेत्राधिकार है। विशेष अदालत स्वयं एक मजिस्ट्रेट नहीं है और यह कोई अदालत भी नहीं है जिससे किसी मामले की प्रतिबद्धता की जाती है।"

26. टी.एन. राज्य बनाम वी. कृष्णास्वामी नायडू, (1979) 4 एससीसी 5 के मामले में, इस न्यायालय ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि क्या आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 1952 के तहत विशेष न्यायाधीश किसी को प्रदत्त शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। सीआरपीसी की धारा 167 के तहत मजिस्ट्रेट ने आरोपी को पुलिस हिरासत में रखने की अनुमति देने के लिए कहा कि एक विशेष न्यायाधीश को आरोपी को सुनवाई के लिए सौंपे बिना अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार है। उनके आधिपत्य ने देखा:

"5. यह ध्यान दिया जा सकता है कि विशेष न्यायाधीश दंड प्रक्रिया संहिता के तहत एक सत्र न्यायाधीश, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश या सहायक सत्र न्यायाधीश नहीं है, हालांकि किसी भी व्यक्ति को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है।विशेष न्यायाधीश जब तक कि व विशेष न्यायाधीश को आरोपी को मुकदमे के लिए सौंपे बिना अपराधों का संज्ञान

लेने का अधिकार है। सत्र न्यायाधीश द्वारा अपराध का विचारण करने का अधिकार क्षेत्र उसे सौंपे जाने के बाद ही है। इसके अलावा सत्र न्यायाधीश मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट मामलों की सुनवाई की प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं। विशेष न्यायाधीश को केवल कुछ उद्देश्यों के लिए सत्र न्यायालय माना जाता है जैसा कि अधिनियम की धारा 8(3) में उल्लिखित है, जबकि उप-धारा 3 का पहला भाग उप-धारा (1) और (2) में दिए गए प्रावधानों को छोड़कर प्रदान करता है। धारा 8 आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1898 के प्रावधान, जहां तक वे इस अधिनियम के साथ असंगत नहीं हैं, विशेष न्यायाधीश के समक्ष कार्यवाही पर लागू होंगे।"

27. रघुबंस दुबे बनाम बिहार राज्य एआईआर 1967 एससी 1167 के मामले में, इस न्यायालय ने इसी तरह के मामले से निपटते हुए कहा कि एक बार मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान ले लिया गया है, वह अपराध का संज्ञान लेता है, न कि अपराधी का और एक बार जब वह आता है इस निष्कर्ष पर कि पुलिस द्वारा भेजे गए व्यक्तियों के अलावा कुछ अन्य व्यक्ति भी शामिल हैं, उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करना उसका कर्तव्य है। अतिरिक्त अभियुक्त को तलब करना उसके द्वारा किसी अपराध का संज्ञान लेने से शुरू की गई कार्यवाही का हिस्सा है।

28. किशुन सिंह बनाम बिहार राज्य (सुप्रा) के मामले में धारा 193, 209 और 319 के तहत न्यायालय का दायरा और शक्ति इस प्रकार देखी गई: -

"16. हमने रघुबंस दुबे और हरेराम के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों के अनुपात से पहले ही संकेत दिया है कि एक बार जब न्यायालय अपराध (अपराधी नहीं) का संज्ञान लेता है तो वास्तविक अपराधियों का पता लगाना न्यायालय का कर्तव्य बन जाता है और यदि इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि पुलिस द्वारा मुकदमे के लिए रखे गए व्यक्तियों के अलावा कुछ अन्य लोग भी अपराध में शामिल हैं, यह अदालत का कर्तव्य है कि उन्हें पहले से नामित लोगों के साथ मुकदमे के लिए बुलाया जाए क्योंकि उन्हें बुलाना केवल संज्ञान लेने की प्रक्रिया का एक हिस्सा होगा। हमने दोनों संहिताओं की धारा 193 की भाषा में अंतर भी बताया है, पुरानी संहिता के तहत सत्र न्यायालय को मूल क्षेत्राधिकार की अदालत के रूप में किसी भी अपराध का संज्ञान लेने से रोक दिया गया था, जब तक कि आरोपी इसके लिए प्रतिबद्ध न हो, जबकि वर्तमान के तहत कोड एम्बार्गो को अभियुक्त शब्द के स्थान पर केस शब्द से प्रतिस्थापित करके पतला कर दिया गया है। इस प्रकार, धारा 193 को स्पष्ट रूप से पढ़ने पर, जैसा कि यह वर्तमान में मौजूद है, एक बार मामला संहिता के तहत एक मजिस्ट्रेट द्वारा सत्र न्यायालय को सौंप दिया जाता है; मूल क्षेत्राधिकार की अदालत के रूप में किसी अपराध का संज्ञान लेने की सत्र न्यायालय की

शक्ति पर लगाया गया प्रतिबंध हटा दिया गया है। मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 209 के तहत मामले को सत्र न्यायालय में सौंपने पर धारा 193 की बाधा हटा दी जाती है, जिससे सत्र न्यायालय को अपराध का संज्ञान लेने के लिए मूल क्षेत्राधिकार के न्यायालय के पूर्ण और अप्रतिबंधित क्षेत्राधिकार का निवेश करना पड़ता है जिसमें सम्मन शामिल होगा। वह व्यक्ति या व्यक्ति जिनकी अपराध के कमीशन में संलिप्तता को प्रथम दृष्टया रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री से इकट्ठा किया जा सकता है। पटना उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने शेख लुत्फुर रहमान के मामले में संहिता की धारा 193 में पुराने संहिता के तहत बदलाव की उचित ही सराहना की:

"इसलिए, धारा 193 के तहत कानून अभी जो कल्पना और प्रावधान करना चाहता है वह यह है कि अपराध बनाने वाली पूरी घटना का संज्ञान सत्र न्यायालय द्वारा प्रतिबद्धता के आधार पर लिया जाना है, न कि प्रत्येक व्यक्तिगत अपराधी को ऐसा प्रतिबद्ध होना चाहिए या यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो सत्र न्यायालय उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने में शक्तिहीन होगा जिनके बारे में मुकदमे की दहलीज

पर ही यह पूरी तरह से आश्वस्त हो सकता है कि वे भी प्रथम दृष्टया अपराध के दोषी हैं... एक बार मामला दर्ज कर लिया गया है, धारा 193 की रोक हटा दी गई है या इसे दूसरे शब्दों में कहें तो यह शर्त पूरी हो गई है कि सत्र न्यायालय को अपराध के किसी भी आरोपी को बुलाने का पूर्ण अधिकार क्षेत्र प्राप्त है।"

हम पुरानी धारा 193 और वर्तमान प्रावधान के बीच सामने आए अंतर से सम्मानजनक सहमत हैं।"

29. विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश से पता चलेगा कि उत्तरदाताओं के खिलाफ समन जारी करते समय अदालत ने जांच के दौरान रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री पर विस्तार से विचार किया है। हम कुछ अनुच्छेदों का उल्लेख करना चाहेंगे, जिन्हें यहां नीचे उद्धृत किया गया है:-

"14. जांच के दौरान यह भी पता चला कि श्री राम नारायण अग्रवाल ने धोखाधड़ी से सोसायटी को नियमित करने के लिए विभिन्न झूठे दस्तावेज खरीदे थे, जिन्हें आरसीएस के कार्यालय में जमा किया गया था। दस्तावेजों का विवरण इस प्रकार है:

सामान्य निकाय बैठक की कार्यवाही दिनांक 15-11-1998 एवं 23-01-2000

कार्यवाही रजिस्टर में 22-11-1998 से प्रभावी कार्यवाही है।

सदस्यता रजिस्टर में सदस्यों की संख्या 101 से आगे है।

15. सामान्य निकाय बैठक (जीबीएम) की कार्यवाही दिनांक 15-11-1998 जो कि सोसायटी के कार्यालय 303 में आयोजित की गई थी। तीसरी मंजिल, सी50, वसंत टॉवर सामुदायिक केंद्र, जनक पुरी जहां 46 सदस्यों के इस्तीफे की मंजूरी दी गई और प्रबंध समिति द्वारा 1996-97 की अवधि के दौरान 35 नए सदस्यों का नामांकन गलत तरीके से दिखाया गया था। इसी प्रकार, जीबीएम दिनांक 23-01-2000 की कार्यवाही में प्रबंध समिति द्वारा 10 प्रमोटर सदस्यों के पंजीकरण की मंजूरी को झूठा दर्शाया गया है। उस जीबीएम में प्रबंध समिति का फर्जी चुनाव कराया जाना दिखाया गया था, जिसमें अध्यक्ष श्री ओपी अग्रवाल, अध्यक्ष श्री. अनिल कुमार शर्मा- उपाध्यक्ष और सोसायटी की प्रबंध समिति के अन्य सभी सदस्य जिनके नाम श्री आर.एन. अग्रवाल, सुश्री सुजाता चौहान, श्री सुधीर अग्रवाल, श्री सीएल बंसल और सुश्री जनक हैं, को झूठे चुनाव कराकर निर्वाचित दिखाया गया है। प्रबंधन समिति। जीबीएम दिनांक 15-11-1998, 23-1-2000 की इन कार्यवाही पर श्री सुधीर अग्रवाल के हस्ताक्षर फर्जी हैं जो श्री आर.एन. अग्रवाल के कहने पर सुश्री सुजाता द्वारा लिखे गए हैं।

16. यह भी पता चला कि सोसायटी के तत्कालीन अध्यक्ष और सचिव क्रमशः श्री एमएलश्री लाल लोधी और श्री भूपिंदर कुमार ने वर्ष 1996-97 के दौरान प्रमोटर सदस्यों के इस्तीफे और नए सदस्यों के नामांकन को कभी मंजूरी नहीं दी थी, जैसा कि जीबीएम दिनांक 15-11-1998 में दिखाया गया है।

17. डीडीए से दिनांक 21-9-1998 का मांग पत्र प्राप्त करने के बाद, सोसायटी के सचिव एसएच भूपिंदर कुमार के हस्ताक्षर के तहत दिनांक 2-11-1998 का एक डाक पत्र आयुक्त (आवास), डीडीए, नई दिल्ली को धोखाधड़ी से प्रस्तुत किया गया था। जिससे भुगतान के लिए अधिक समय मांगा गया।

18. जांच से पता चला कि श्री आरएन अग्रवाल ने श्री भीम सिंह माहूर के साथ आपराधिक साजिश रचकर धोखाधड़ी से श्री मिश्री लाल (अध्यक्ष), श्री भूपिंदर कुमार (सचिव) और श्रीमती केला देवी (कोषाध्यक्ष) द्वारा हस्ताक्षरित दिनांक 15-11-1998 का एक पत्र प्राप्त किया।) और इसे प्रबंधक, दिल्ली राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड, दरिया "गंज, नई दिल्ली को भेज दिया, जिसमें गलत तरीके से कहा गया कि श्री अनिल कुमार शर्मा, श्री आरएन अग्रवाल और श्री ओम प्रकाश अग्रवाल को नए प्रबंध में क्रमशः अध्यक्ष, सचिव और

कोषाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। उक्त सोसायटी की समिति एवं उक्त पदाधिकारी को उक्त सोसायटी के बैंक खातों को संचालित करने के लिए अधिकृत किया गया है और इस प्रकार उपरोक्त सभी नामित आरोपियों ने उक्त सोसायटी के बैंक खाते के संचालन पर फर्जी तरीके से नियंत्रण कर लिया था।

xxxxx

20. जांच में आगे पता चला कि सोसायटी के एक प्रमोटर सदस्य श्री गणेश झा ने दिनांक 26.6.2000 और 5.10.2000 को आरसीएस, नई दिल्ली के कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी कि सोसायटी ने उन्हें डीडीए द्वारा भूमि आवंटन के लिए सूचित नहीं किया था और न ही उनकी मांग की थी। भूमि की लागत में योगदान का हिस्सा और उन्हें संदेह था कि सचिव ने सदस्यता रजिस्टर में धोखाधड़ी की है। सोसायटी ने बिना किसी गलत मकसद के सदस्यों की बैठक बुलाए गुपचुप तरीके से पंजीकृत कार्यालय स्थानांतरित कर दिया और न ही उन्हें सोसायटी की किसी भी बैठक में शामिल होने के लिए बुलाया।

21. जांच में यह भी पता चला है कि श्री लीला कृष्ण सेठ ने शिकायतों में किए गए आवंटन पर सत्यापन करने के लिए

श्री जफर इकबाल को नियुक्त किया था, जिन्होंने श्री आर.एन. अग्रवाल के आदेश पर झूठी सत्यापन रिपोर्ट दी थी जिसमें उन्होंने धोखाधड़ी से प्रमाणित किया था कि चुनाव संतोषजनक थे। 15.11.98 को सोसायटी द्वारा आयोजित किया गया और आरोपी व्यक्तियों को सोसायटी द्वारा क्लीन चिट देकर बेईमानी से मदद की गई।

22. जांच से यह भी पता चला कि उपरोक्त आपराधिक साजिश में लीला कृष्ण सेठ, तत्कालीन सहायक रजिस्ट्रार, श्री जफर इकबाल, तत्कालीन इंस्पेक्टर ग्रेड-III ने श्री आर. एन अग्रवाल और श्री ओ के साथ आपराधिक साजिश में शामिल होकर अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया था। पग्गरवाल ने डीडीए को धोखा देने के इरादे से सोसायटी के पक्ष में डीडीए से जमीन का आवंटन और कब्जा प्राप्त कर लिया।"

30. विशेष न्यायाधीश ने जांच के दौरान रिकॉर्ड पर लाई गई सभी सामग्रियों पर विचार किया और मिस स्विल लिमिटेड बनाम दिल्ली राज्य और अन्य (2001) 6 एससीसी 670 के मामले में इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया; निसार और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1995) 2 एससीसी 23;1995 सीआरएल एलजे 2118; किशन सिंह बनाम बिहार राज्य (सुप्रा); रघुबंस दुबे बनाम बिहार राज्य, (1967) 2 एससीआर 423, इस निष्कर्ष

पर पहुंचे कि उत्तरदाता अपराध में शामिल थे और परिणामस्वरूप उनके खिलाफ समन जारी किए गए थे।

31. आक्षेपित आदेश पारित करते समय उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा करने के बजाय अनिरुद्ध सेन के मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश के निर्णय (प्रथम दृष्टया) का पालन करते हुए विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को उलट दिया। इसलिए, प्रतिवादियों के खिलाफ विशेष न्यायाधीश द्वारा समन जारी करने को रद्द करने वाला उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश कानून की दृष्टि से गलत है और इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है। हालाँकि, इस स्तर पर विशेष न्यायाधीश के लिए यह आवश्यक नहीं था कि वह मामले की जांच करने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए सीबीआई को निर्देश जारी करें।

32. उपरोक्त कारणों से हम इन अपीलों को स्वीकार करते हैं और उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश को रद्द करते हैं और ऊपर बताए अनुसार सीबीआई को जारी निर्देश को छोड़कर विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को बहाल करते हैं।

निधि जैन

अपीलों की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता निशा पालीवाल द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।